सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

RNI No: UPHIN/2023/86769

www.swarajindianews.com

swarajindia2023@gmail.com swarajindianews swarajindianews

मूल्य: ₹ 02

सांध्यकालीन समाचार पत्र

# स्वराज इंडिया

कानपुर, शुक्रवार, 27 जून, 2025
वर्ष: 02, अंक: 176, पृष्ठ: 8+4

चार घंटे में पोस्टमार्टम परिवार से नहीं लिया जाएगा वीडियोग्राफी का पैसा

» Pg 12

इनसाइड कानपुर में शहरी विकास का नया अध्याय... » Pg 00

### भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में तनातनी के चलते तीर्थयात्रा पर लगी थी रोक

# 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो/एजेंसी

**नई दिल्ली।** भगवान शिव का निवास माने जाने वाले पवित्र कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा पर निकले भारतीय श्रद्धालुओं का पहला जत्था तिब्बत पहुंच गया। यह यात्रा पांच वर्षों के लंबे अंतराल के बाद शुरू हुई है। जब भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में तनातनी के चलते तीर्थयात्रा पर रोक लगी थी।

चीन में भारत के राजदूत शू फेडोंग ने सौशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कहा, कि यह जानकर खुशी हुई कि तीर्थयात्रियों का पहला जत्था चीन के शिजांग (तिब्बत) स्वायत्त क्षेत्र स्थित मपान युन त्सो (मानसरोवर) झील पर पहुंच गया है। 36 भारतीय तीर्थगात्रिगों के इस पहले जत्थे को ऐतिहासिक माना जा रहा है। यह वह समूह है जो चीन की जमीन से होकर कैलाश मानसरोवर पहुंचा है, जो कि भारत-चीन संबंधों में एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।

भारतीय श्रद्धालुओं का पहला जत्था तिब्बत पहुंच गया।

पिछले साल रूस में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी चिनपिंग में मुलाकात हुई और दानों पक्षों में द्विपक्षीय संबंधों को फिर से पटरी पर लाने पर सहमति जताई थी। कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली को दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल गाना जा रहा है। लंबे समय से बंद पड़ी यह यात्रा अब माचिकारिक रूप से एक नई शुरुआत की और बढ़ रही है।

## कैलाश पर्वत के दर्शन

कैलाश पर्वत को भगवान शिव और मां पार्वती का निवास स्थान माना जाता है. यह पर्वत पारहिमालय पर्वतमाला का हिस्सा है और समुद्र तल से करीब 21,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है. यहां से मानसरोवर झील और राक्षस ताल झील भी दिखाई देती हैं।

### कैलाश मानसरोवर यात्रियों को मदद

## एक लाख देगी योगी सरकार

कैलाश मानसरोवर यात्रियों को यूपी की योगी सरकार एक-एक लाख रुपये देगी। यह आर्थिक मदद केवल यूपी के निवासियों को ही मिलेगा। इस बारे में प्रमुख सचिव धर्मार्थ कार्य मुकेश मेश्राम ने शुक्रवार को जानकारी दी। भारत सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा में सम्मिलित होने वाले यात्रियों के अतिरिक्त अपने व्यक्तिगत स्रोतों से तथा प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से यात्रा पूर्ण करने वाले यात्रियों को भी अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके लिए पात्रा पूर्ण करने वाले यात्रियों को धर्मार्थ कार्य विभाग की वेबसाइट www.updharmarthkarya, in पर 90 दिवस के भीतर आवेदन करना होगा।

» मानसरोवर झील को ब्रह्मा के मन से बना हुआ माना जाता है और इसे पवित्र जल का स्रोत माना जाता है. यहां से सरयू, सतलुज, सिंधु और बह्मपुत्र नदियां निकलती हैं. इस झील का पानी मीठा होता है और इसे धामिज्क दृष्टि से बहुत पचित्र माना जाता है.

### कड़ी सुरक्षा

### अमरनाथ यात्रा से पहले उधमपुर के बसंतगढ़ में आतंकियों से मुठभेड़

# जैश-ए-मोहम्मद का एक आतंकी ढेर, तीन की घेराबंदी

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

**जम्मू।** श्री अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले उधमपुर के बसंतगढ़ में सुरक्षाबलों मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद के एक आतंकी को ढेर कर दिया। वहीं, बचे तीन आतंकियों की घेराबंदी कर रखी है। इनके सफाए के लिए सेना और पुलिस ने ऑपरेशन बिहाली शुरू किया है।

बताया जा रहा है कि जैश-ए-मोहम्मद के ये आतंकी पिछले एक वर्ष से सक्रिय रहे हैं।आईजी जम्मू भीमसेन टूटी ने बताया कि पुख्ता सूचना के आधार पर सुबह करीब 8:30 बजे सुरक्षाबलों और पुलिस ने बसंतगढ़ के बिहाली इलाके के जंगलों में तलाशी अभियान शुरू किया। सामना होते ही आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सेना की व्हाइट नाइट कोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बताया कि जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी मारा गया।

**पैरा कमांडो ने भी मोर्चा संभाला** : आतंकी एक नाले के नजदीक छिपे हुए हैं। वे भाग न सकें, इसलिए घेराबंदी की है। आतंकियों को ढेर करने के लिए सेना ने पैरा कमांडो भी उतार दिए हैं। लगातार बारिश और धुंध के बावजूद ऑपरेशन बिहाली जारी है। पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकियों को पनाह देने वाले मददगार तो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन दहशतगर्द अब भी पकड़ से बाहर हैं। इतना स्पष्ट हो गया है कि हमला करने वाले तीन आतंकी थे। तीनों लश्कर-ए-तैयबा के पाकिस्तानी नागरिक हैं।

जैश-ए-मोहम्मद के एक आतंकी मुठभेड़ में हुआ ढेर।

# बिल्हौर में फिर एक और चोरी की वारदात !

**स्वराज इंडिया संवाददाता**

बिल्हौर (कानपुर)। बुधवार की रात परिवार के साथ छत पर चैन की नींद सो रहे चैन निवादा गांव में किसान शिवमंगल राजपूत के घर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला। चोर ज़ेवर व नकदी समेत लाखों का माल पार कर फरार हो गए। सुबह जब चैन की नींद लेकर उठे परिजनों ने घर का बिखरा समान देखा तो बेचैन हो गए। इसके बाद उन्हें घर में चोरी की जानकारी हुई। जानकारी पाकर पुलिस मौके पर जाँच करने पहुंची। पीड़ित किसान ने पुलिस में चोरी की तहरीर दी है। पुलिस जल्द घटना का खुलासा करने का दावा कर रही है।

- » चैन निवादा गांव में चैन की नींद सो रहे परिवार के घर में चोरी
- » एक के बाद एक वारदातें, चोरों के हौसले बुलंद
- » भाजपा नेता के घर चोरी की गुत्थी सुलझी नहीं कि सामने आ गई एक नई वारदात
- » पुलिस की गश्त, कार्रवाई और दावे हुए सब नाकाफी साबित

## पुलिस ने भाजपा नेता के घर हुई चोरी का केस दर्ज किया

बिल्हौर। परिवार व दोस्तों संग बाहर घूमने गए भाजपा नेता के घर में बीते दिनों हुई चोरी के मामले में पुलिस ने चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। 25 तारीख को लौटे भाजपा नेता विक्रम मिश्रा के घर में हुई चोरी की समीक्षा की। पीड़ित ने पुलिस से बताया है कि ढाई लाख रुपए नगद और कई कीमती गहने, कैमरा का डीवीआर चोरी हुआ है। पुलिस में भाजपा नेता को जल्द चोरी का खुलासा करने का आश्वासन दिया है। पुलिस क्षेत्र के हर संदिग्ध पर नजर बनाए हुए हैं। मामले में पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ भी की लेकिन नतीजा अभी कुछ नहीं निकला।

मालूम हो कि बिल्हौर क्षेत्र में चोरी की वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताज़ा मामले में पुलिस अभी भाजपा नेता विक्रम मिश्रा के घर हुई चोरी की जांच में ही उलझी थी कि चोरों ने एक और घर को अपना निशाना बना डाला। लगातार हो रही वारदातों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इलाके में बीते कुछ हफ्तों में आधा दर्जन से ज्यादा चोरियां हो चुकी हैं, लेकिन एक भी मामले का पुलिस खुलासा नहीं कर पाई है। चोर कानून को ठेंगा दिखाते हुए सरेआम पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। बढ़ रही चोरी की घटनाओं से स्थानीय लोगों में भय का माहौल है।

अब देखना यह होगा कि पुलिस इन बढ़ती घटनाओं पर कब तक लगाम लगाती है, या फिर ये भी एक और अज्ञात चोर की फाइल बनकर रह जाएगी।

# मलिहाबाद में थाने से 100 मीटर दूर चल रही थी असलहा फैक्टरी

## » पुलिस ने देर रात मारा छापा, एक हिरासत में

**स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो**

मलिहाबाद। मलिहाबाद के एक गांव में थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर एक अवैध असलहा फैक्टरी चल रही थी। अंदेशा है कि हिरासत में लिया गया आरोपी सलाउद्दीन प्रदेश में बड़े पैमाने पर असलहों की सप्लाई करता है। उसे हिरासत में ले लिया गया है।

मलिहाबाद के मिर्जागंज गांव में थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर हकीम सलाउद्दीन के मकान में अवैध असलहा फैक्टरी चल रही थी। इसकी सूचना पर बृहस्पतिवार देर रात पुलिस ने छापा मारा। करीब पांच घंटे के सर्च ऑपरेशन में बड़ी संख्या में अवैध असलहे और कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने सलाउद्दीन को हिरासत में ले लिया है।

इससे पहले मुखबिर की सूचना पर मलिहाबाद और रहीमाबाद पुलिस की संयुक्त टीम ने छापा मारा। इस दौरान अवैध असलहे बनाने के उपकरण भी मिले हैं।

एडीसीपी नॉर्थ जितेंद्र दुबे के मुताबिक बृहस्पतिवार शाम छह बजे महिलाबाद पुलिस को मिर्जागंज गांव में एक हकीम के घर असलहे होने की जानकारी मिली। इस पर एसीपी मलिहाबाद और दोनों थानों की पुलिस ने घर पर छापा मारा। इस दौरान हकीम सलाउद्दीन, उसकी पत्नी और बेटी मौजूद थी।

पांच घंटे तक चली तलाशी में पुलिस को भारी संख्या में असलहे मिले। इस संबंध में पुलिस के पूछताछ करने पर सलाउद्दीन कोई जवाब नहीं दे सका। सूत्रों के मुताबिक सलाउद्दीन असलहों का शौकीन है। आशंका है कि उसके पास विदेशी असलहे भी हैं।

**दवाखाना चलाता था सलाउद्दीन**

स्थानीय लोगों ने बताया कि सलाउद्दीन दवाखाना चलाता थे। कुछ महीने पहले उनके तीन परिजनों की हत्या हो गई थी। सलाउद्दीन की एक बेटी नार्वे में पढ़ाई करती है और दूसरी इंटीग्रल में पढ़ रही है। पुलिस ने कुछ अन्य संदिग्धों को भी पकड़ा है।

पुलिस की कार्रवाई के बाद स्थानीय लोग भी हैरत में हैं। अंदेशा है कि सलाउद्दीन बड़े स्तर पर प्रदेश में असलहों की सप्लाई कर रहा था। कार्रवाई के दौरान पुलिस को उसके घर में ओवैश नाम का युवक भी मिला।

# कानपुर में शहरी विकास का नया 'अध्याय'

राहुल पांडेय, स्वराज इंडिया

कानपुर। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के तत्वावधान में कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) द्वारा न्यू चकेरी हवाई अड्डे के निकट एयरो सिटी और आईआईटी कानपुर के पास नॉलेज सिटी परियोजनाओं का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इन परियोजनाओं की कुल लागत 1240 करोड़ रुपये आंकी गई है, जो शहर को आवासीय, वाणिज्यिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में एक नया केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये परियोजनाएं न केवल कानपुर को आर्थिक प्रगति प्रदान करेंगी, बल्कि रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जरूरी कदम साबित होगी।

- » एयरो सिटी और नॉलेज सिटी परियोजनाओं पर काम शुरू
- » सीएम योगी के मार्गदर्शन में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग करवा रहा है निर्माण कार्य
- » न्यू चकेरी हवाई अड्डे के पास 300 एकड़ में बन रही है एयरोट्रोपोलिस, एयरो सिटी
- » एयरोट्रोपोलिस, एयरो सिटी आवासीय और वाणिज्यिक गतिविधियों का बनेगी केंद्र
- » नॉलेज सिटी का 880 करोड़ रुपये की लागत हो रहा है आईआईटी कानपुर के पास विकास
- » शिक्षा, अनुसंधान और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देगी कानपुर की नॉलेज सिटी

### एयरोट्रोपोलिस, एयरो सिटी आवासीय और वाणिज्यिक गतिविधियों का बनेगी केंद्र

सीएम योगी आदित्यनाथ के विजन के मुताबिक आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, प्रदेश के शहरों में इंफ्रास्टकचर और आवसीय सुविधाओं का विश्वस्तरीय विकास कर रहा है। इस दिशा में केडीए लगभग 37,263 करोड़ रुपये की लागत से कानपुर शहर के कायाकल्प के लिए 61 परियोजनाओं का निर्माण कर रहा है। जिसमें से न्यू चकेरी हवाई अड्डे के पास 360 करोड़ रुपये की लागत से एयरोट्रोपोलिस, एयरो सिटी का निर्माण किया जा रहा है। 300 एकड़ क्षेत्र में विकसित हो रही एयरो सिटी परियोजना का निर्माण सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल होगा। एयरो सिटी, एयरोट्रोपोलिस के निर्माण का उद्देश्य हवाई अड्डे के आसपास एक मेट्रोपॉलिटन उपक्षेत्र का निर्माण करना है। जो एक साथ आवासीय और वाणिज्यिक गतिविधियों का केंद्र होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग-34 से सीधी कनेक्टिविटी के कारण यह क्षेत्र निवेशकों और नागरिकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है।

एयरो सिटी में चरणबद्ध विकास के तहत विभिन्न अत्याधुनिक सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है, जो कानपुर की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के साथ प्रदेश के आर्थिक एवं शहरी विकास में मील का पत्थर साबित होगा। यह परियोजना हवाई यातायात में वृद्धि और क्षेत्र में बढ़ते आवागमन को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है। ये परियोजना केडीए के लिए आय के भी नये अवसर प्रदान करेगा।

शिक्षा,अनुसंधान और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देगी नॉलेज सिटी

केडीए की आईआईटी कानपुर के पास विकसित हो रही नॉलेज सिटी परियोजना शिक्षा और अनुसंधान का नया केंद्र बन रही है। 359 एकड़ में बन रही नॉलेज सिटी परियोजना की लागत लगभग 880 करोड़ रुपये है।

यह परियोजना भी पीपीपी मॉडल के तहत विकसित हो रही है। नॉलेज सिटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षा, अनुसंधान और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना है। नॉलेज सिटी में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी), तकनीकी विश्वविद्यालय, अनुसंधान केंद्र, जैव-प्रौद्योगिकी संस्थान, विज्ञान संग्रहालय और प्रशिक्षण संस्थान जैसे प्रमुख प्रोजेक्ट भी प्रस्तावित हैं। जो कानपुर को शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के हब के तौर पर विकसित करेगा। नॉलेज सिटी के पास बन रही आउटर रिंग रोड (ओआरआर) और 60 मीटर चौड़ी दक्षिणी धमनी सड़क इस क्षेत्र को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे।

आईआईटी कानपुर की निकटता के कारण यह परियोजना शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग के लिए एक माडल के रूप में विकसित होगी। इन परियोजनाओं के निर्माण से एक ओर तो कानपुर शहर की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी, साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। वहीं दूसरी ओर ये परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के आर्थिक और शहरी ढ़ाचागत विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेंगी।

## एयरो सिटी और नॉलेज सिटी के प्रमुख तथ्य

- एजेंसी- केडीए
- लागत-360 करोड़ रुपये
- क्षेत्रफल- 300 एकड़
- स्थान- न्यू चकेरी हवाई अड्डा
- विकास मोड- पीपीपी
- उपयोग-आवासीय और वाणिज्यिक
- कनेक्टिविटी- एनएच-34 से सीधी पहुंच

नॉलेज सिटी

- एजेंसी- केडीए
- लागत-880 करोड़ रुपये (भूमि अधिग्रहण सहित)
- क्षेत्रफल- 359 एकड़
- स्थान- आईआईटी कानपुर के निकट
- विकास मोड-पीपीपी
- उपयोग- संस्थागत (एनआईडी, तकनीकी विश्वविद्यालय, अनुसंधान केंद्र, जैव-प्रौद्योगिकी, विज्ञान संग्रहालय आदि)
- कनेक्टिविटी- बाहरी रिंग रोड और 60 मीटर चौड़ी सड़क, प्रस्तावित आउटर रिंग रोड

# लोन दफ्तर की आड़ में गंभीर अपराधों का धंधा करती है 'कानपुर की ठग कन्या'

**प्रमुख संवाददाता दैनिक स्वराज इंडिया**

कानपुर। एक युवती जिसे स्वराज इंडिया 'ठग कन्या' के नाम से संबोधित कर रहा है, वो लोन दफ्तर की आड़ में एक संगठित अपराध तंत्र चला रही है। उसने शहर में एक फाइनेंस ऑफिस खोल रखा है, जहां बाहर से तो यह 'लोन सहायता' केंद्र दिखता है, लेकिन अंदर चल रही गतिविधियां चौंकाने वाली हैं। ऑफिस में काम कर रही कई युवतियां कीपैड मोबाइल उसमें फर्जी सिमकार्ड और कानपुर तथा कानपुर से सटे जिले छोड़कर तमाम जिलों का कॉलिंग डाटा लेकर हर दिन नए युवकों को फोन करती हैं। ये नंबर उन लोगों के होते हैं जो विवाह के लिए लड़की की तलाश में रहते हैं। कॉल पर यह लड़कियां खुद को मैरिज ब्यूरो का स्टाफ बताकर 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस मांगती हैं, जो सीधे ठग कन्या के खाते में जाता है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाने वाले युवक को एक लड़की का मोबाइल नंबर दिया जाता है यह बोलकर कि यह लड़की आपके लिए परफेक्ट है जो असल में उसी ठग कन्या गिरोह की सदस्य होती है।

वह लड़की युवक से प्रेम की बातें करती है, विश्वास जीतती है, और धीरे-धीरे उससे पैसे ठगती है। यह पैसा ठग कन्या की जेब में जाता है, जबकि ये सब करने वाली लड़की को मामूली मेहनताना दिया जाता है।

» **लोन ऑफिस की आड़ में फर्जी मैरिज ब्यूरो, देह व्यापार, न्यूड कॉलिंग, पोर्नोग्राफी और मानव तस्करी का केंद्र**

» **मैरिज ब्यूरो के नाम पर युवकों को ठगी के प्रेम-जाल में फंसाकर की जाती है अवैध वसूली**

» **शादी, फाइनेंस और टेली कॉल के नाम पर अश्लील जाल एक युवती के नेटवर्क में दर्जनों अपराधों की परतें**

न्यूड कॉलिंग, ब्लू फिल्म और मानव तस्करी लोन दफ्तर बन गया है जुर्म का अड्डा

यह ठगी का खेल यहीं नहीं रुकता। इसी ऑफिस के अंदर चलता है देह व्यापार, न्यूड वीडियो कॉलिंग, ब्लू फिल्म की रिकॉर्डिंग और मानव तस्करी का रैकेट।

पब्लिक की नज़र में लोन कराने के नाम पर आने वाले लोग असल में होते हैं देह व्यापार के ग्राहक। शाम के वक्त जब कॉल सेंटर की लड़कियां घर लौटती हैं, ठग कन्या थोड़े वक्त के लिए कुछ 'बिजनेस पार्टनरों' के साथ दफ्तर में ही ठहरती है। यही लोग पोर्न फिल्म निर्माण, न्यूड वीडियो कॉलिंग, और महिला तस्करी जैसे जघन्य अपराधों से जुड़े होते हैं। युवतियों को पैसों का लालच देकर न्यूड वीडियो कॉल्स करवाई जाती हैं, और फिर उन वीडियो का गलत इस्तेमाल होता है कभी ब्लैकमेलिंग, तो कभी पोर्न साइट्स पर बिक्री। यह कोई साधारण ठगी नहीं यह एक संगठित, सुनियोजित और मानवता के विरुद्ध घिनौना धंधा है।

**जल्द होगा ठग कन्या के गुनाहों का पर्दाफाश**

स्वराज इंडिया की टीम इस संगठित आपराधिक नेटवर्क की गहराई से तहकीकात कर चुकी है। बहुत जल्द एक विशेष रिपोर्ट के माध्यम से हम ठग कन्या की असल पहचान, उसके सहयोगियों का चेहरा, ब्लू फिल्म, न्यूड वीडियो कॉलिंग के धंधे में उसकी संलिप्तता, और मानव तस्करी से जुड़े नेटवर्क की पूरी परतें खोलने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक लोन ऑफिस की कहानी नहीं है, यह उन काले कारोबारियों की आपराधिक गाथा है, जो कानपुर जैसे शहर में कानून की आंखों में धूल झोंकते हुए बेखौफ फल-फूल रहे हैं। स्वराज इंडिया इस गुनाह के पर्दे को उठाकर उसे जनता और कानून के सामने लाने की तैयारी कर चुका है।

# कुछ अभिभावक स्कूलों के विलय को बता रहे हैं बेहतर

**स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो**

**कानपुर । उत्तर प्रदेश में कम छात्र संख्या वाले परिषदीय विद्यालयों का बड़े विद्यालयों में विलय करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इस प्रक्रिया के तहत 50 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों को पास के बड़े विद्यालयों में समायोजित किया जा रहा है। महानिदेशक कंचन वर्मा ने सभी जिलों के अधिकारियों को अभिभावकों के साथ बैठक कर विलय के फायदे बताने के निर्देश दिए हैं उन्होंने सभी एडी बेसिक, बीएसए और बीईओ को निर्देश देते हुए कहा है कि डीएम सीडीओ और डीपीआरओ से समन्वय बनाकर विद्यालयों के विलय की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण करें। बता दें विभाग द्वारा इस कदम का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और संसाधनों का बेहतर उपयोग करना बताया जा रहा है।**

अधिकारियों का दावा है कि विद्यालयों के विलय की प्रक्रिया सोच-समझकर और स्थानीय

» **अधिकारियों का दावा है कि विद्यालयों के विलय की प्रक्रिया सोच-समझकर और स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर की जा रही है**

आवश्यकताओं के आधार पर की जा रही है। कई अभिभावकों का भी कहना है कि कम छात्र संख्या वाले स्कूलों का विलय करना सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है खासकर उन स्कूलों में जहाँ छात्रों की संख्या 40 या 50 से कम है। ऐसे स्कूलों में शिक्षकों और संसाधनों का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है

और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है। कुछ का तो यह तक कहना है कि सरकार एक स्कूल में जितना रुपए खर्च करती है उतने रुपए में सरकारी स्कूल के बच्चों को अमेरिका के उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थान में पढ़ाया जा सकता है।

वहीं कुछ शिक्षक संगठनों का कहना है कि स्कूल मर्जर प्रक्रिया आरटीई एक्ट का खुला उल्लंघन है।

यह अधिनियम स्पष्ट रूप से निर्देशित करता है कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए विद्यालय अधिकतम 1 किलोमीटर और कक्षा 6 से 8 तक के लिए अधिकतम 3 किलोमीटर की परिधि में होना चाहिए। यह प्रावधान न केवल दूरी को कम करता है बल्कि बच्चों के लिए शिक्षा को सहज, सुलभ और सशक्त बनाता है फिर भी सरकार मनमाने तौर पर स्कूलों को मर्ज कर रही है।

## सम्पादकीय

# चीन-केंद्रित एससीओ की असलियत बेनकाब

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के क्विंगदाओ में संपन्न शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ सम्मेलन समाप्ति के बाद जारी साझा बयान पर हस्ताक्षर करने से मना करके आतंकवाद पर भारतीय पक्ष को ही पुष्ट किया है। जिसके चलते दो दिवसीय सम्मेलन की समाप्ति पर ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी नहीं हो सकी। दरअसल,भारत चाहता था कि अंतिम दस्तावेज में आतंकवाद को लेकर भारतीय चिंताओं को जगह दी जाए। रक्षामंत्री ने आतंकवाद की जड़ों पर प्रहार करने की भारत की नई नीति की रूपरेखा सम्मेलन में रखी। उनका कहना था कि संगठन के सदस्य देशों को सामूहिक सुरक्षा से उत्पन्न चुनौती के मुकाबले के लिये एकजुट होना चाहिए। उनका मानना था कि कट्टरता, उग्रवाद और आतंकवाद हमारी शांति, सुरक्षा और विश्वास को कम कर रहे हैं। यह भी कि आतंकवाद पर तार्किक प्रहार किए बिना सदस्य देशों में शांति व समृद्धि संभव नहीं है। उन्होंने उन तत्वों को बेनकाब करने का प्रयास किया जो आतंकवाद को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिये उसे प्रश्रय देते हैं। उनका मानना था कि एससीओ आतंकवाद पर दोहरे मापदंड अपनाने के बजाय इसको प्रश्रय देने वाले देशों की आलोचना करे। सम्मेलन में रक्षामंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की तार्किकता को बताया और पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले में पर्यटकों को धार्मिक पहचान के आधार पर गोली मारी गई। जिसकी जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकी समूह घोषित लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े टीआरएफ ने ली थी। इसके बाद भारत ने फैसला किया कि हम आतंकवाद के केंद्रों को निशाना बनाने से पीछे नहीं हटेंगे। उनका मानना था कि आतंकवाद पर दोहरा रवैया अपनाए बिना एससीओ को पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करनी चाहिए। दरअसल, पहलगाम आतंकी हमले के प्रतिकार में भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह स्पष्ट कर दिया कि भारत अब पाकिस्तान पोषित आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने के लिये तैयार नहीं है।पहलगाम की घटना दुनिया के सामने स्पष्ट थी और दुनिया के तमाम देशों ने इसकी निंदा भी की। लेकिन पाकिस्तान और उसके करीबी सहयोगियों के नापाक इरादों को दुनिया को बताने तथा भारत की बात हर देश तक पहुंचाने के लिए हमने बहु-पक्षीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर में भेजे। लेकिन पाकिस्तान के सदाबहार दोस्त चीन के दबदबे वाले शंघाई सहयोग संगठन ने सम्मेलन के समापन पर जारी ज्वाइंट स्टेटमेंट में पहलगाम की घटना को नजरअंदाज किया। जिससे पता चलता है कि भारत की आतंकवाद पर नई नीति को और ढंग से समझाने की जरूरत है। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि मेजबान चीन, एससीओ का प्रमुख संस्थापक सदस्य और उस पाक का सदाबहार मित्र है, जिसकी जमीन से पहलगाम साजिश को अंजाम दिया गया। ऐसे में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह द्वारा ज्वाइंट स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर न करना भारत की नाराजगी जाहिर करने की दिशा में सही कदम ही है। उन्होंने सदस्य देशों को स्पष्ट किया कि सीमा पार से चलाये जा रहे आतंकवाद पर दोहरे मापदंडों के लिये कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सदस्य देशों को उन देशों की आलोचना करने से नहीं हिचकना चाहिए जो आतंकवाद को राज्य की नीति के साधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। निस्संदेह, संगठन ने भारतीय पक्ष पर ध्यान न देकर अपने मंसूबों को उजागर किया है। ऐसे में संगठन के सदस्य देशों में विश्वास, मित्रता और संबंधों को मजबूत बनाने के लक्ष्य पूरा होना संदिग्ध ही है।

# क्रिकेट का साम्राज्य और सामूहिक सम्मोहन

अविजीत पाठक

**क्रिकेट एक बेहद लाभदायक व्यापारिक साम्राज्य में तब्दील हो गया है। चूंकि नवउदारवाद के युग में बाजारवाद को एक गुण माना जाता है, क्रिकेट- जी हां, एक दिवसीय क्रिकेट अपनी तात्कालिकता, जोशीलेपन, विज्ञापन मशीनरी और तकनीकी रूप से परिष्कृत लाइव कवरेज के साथ- एक बिक्री योग्य वस्तु बन गया है।हाल ही में, बिहार के ग्रामीण बच्चों के एक समूह के साथ बातचीत में, मैंने उनके पसंदीदा खेल के बारे में पूछा। उन्होंने बड़े उत्साह के साथ जवाब दिया, 'क्रिकेट'। मैंने आगे जानना चाहा; और इस बार उनके पसंदीदा क्रिकेटर का नाम पूछा। और भी जोश के साथ जवाब आया, 'विराट कोहली'। इसने मुझे संवाद आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया और पूछा, क्या आप मुझे किसी महान हॉकी खिलाड़ी या महिला पहलवान का नाम बता सकते हैं?**

इस बार गहरी खामोशी छा गई। वास्तव में, यह चुप्पी बताती है कि किस तरह क्रिकेट ने हमारी चेतना पर कब्ज़ा जमा लिया है और अंततः ध्यानचंद जैसे हॉकी के दिग्गज, इंदर सिंह जैसे फुटबॉलर या विनेश फोगाट जैसी महिला पहलवान से जुड़ी हमारी सामूहिक यादों को मिटा दिया है।वास्तव में, क्रिकेट सर्वव्यापी हो गया है; चाहे गांव हों या शहर; यह झुग्गियों में भी है और गेट लगी कालोनियों में भी; और ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक कांस्टेबल से लेकर रसोई में काम करने वाली गृहिणी तक; या कॉर्पोरेट कार्यकारी से लेकर युवा छात्र तक – हर कोई क्रिकेट से सम्मोहित है। इसलिए, इसमें कोई हैरानी नहीं कि और जैसा कि एक अनुमान बताता है, हाल ही में आयोजित आईपीएल (इंडियन प्रीमियर लीग) को देखने वाले टीवी दर्शकों की संख्या 50 करोड़ से अधिक रही। ऐसा लगता है कि क्रिकेट सिर्फ एक अन्य खेल नहीं है। यह एक तमाशा बन चुका है; एक बहुत बड़े पैमाने पर उपभोग की वस्तु; और सबसे बढ़कर, एक ऐसी आधुनिक पौराणिक कथा, जो जीवन शैली बेचती है– ग्लैमर, पैसा और स्टारडम। असल में, इस घटनाक्रम को समझने के लिए हमें तीन चीजों को समझने की जरूरत है।पहली, क्रिकेट एक बेहद लाभदायक व्यापारिक साम्राज्य में तब्दील हो गया है। चूंकि नवउदारवाद के युग में बाजारवाद को एक गुण

माना जाता है, क्रिकेट– जी हां, एक दिवसीय क्रिकेट अपनी तात्कालिकता, जोशीलेपन, विज्ञापन मशीनरी और तकनीकी रूप से परिष्कृत लाइव कवरेज के साथ– एक बिक्री योग्य वस्तु बन गया है। वास्तव में, हम आईपीएल को एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल के रूप में इस तरह समझ सकते हैं, जब हमें यह पता चले कि इसने केवल घरेलू मीडिया राजस्व के ज़रिए ही 1.21 बिलियन डॉलर से कम नहीं कमाए हैं। और यह मत भूलिए कि बहुत सारे क्रिकेट जुआ एप्लीकेशन सभी हैं– यहां तक कि बड़े क्रिकेटरों द्वारा प्रचारित। तो इसमें क्या हैरानी कि आईपीएल सीजन के दौरान 34 करोड़ से ज्यादा भारतीयों ने इस जुएबाजी में हिस्सा लिया और दुनियाभर से हुई कमाई 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा की रही। जब मैं इन आंकड़ों को देखता हूं, तो मुझे फटे कपड़ों वाला वह ग्रामीण लड़का याद आता है, जो विराट कोहली को अपना हीरो मानता है। मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूं कि उसका पसंदीदा क्रिकेटर भी एक 'उत्पाद' या 'ब्रांड' ही है; और इस बार उसकी 'नीलामी कीमत' सिर्फ़ 21 करोड़ रुपये थी; और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु नामक एक कंपनी ने उसे खरीद लिया। उसने मुझे बेहद आश्चर्य से देखा।

सिर्फ़ इतना ही नहीं। बाज़ारवाद की खींच इतनी अधिक कि यदि आप किसी भी आईपीएल टीम के खिलाड़ियों की जर्सी पर अलग-अलग प्रायोजकों के प्रतीक चिन्ह (लोगो) देखें, तो लगेगा मानो वाकई 'चलते-फिरते बिल बोर्ड' बन चुके हैं। दरअसल, खेलते वक्त भी वे आपको यह उत्पाद खरीदने के लिए लालायित करते हैं। यही मुद्रा घुमाने का चक्र है। आप और हम पागल हो जाते हैं, आईपीएल की टिकट ब्लैक में खरीदते हैं या घंटों टीवी के सामने बैठकर ज़िंदगी की एकरसता से उबरने के लिए क्रिकेट देखते हैं।

# उर्वरक नीति में बदलाव अब समय की मांग

## कृषि सुधार

डॉ. वीरेन्द्र सिंह लाठर

**उर्वरक सब्सिडी का प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण के रूप में किये जाने का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सही लाभार्थियों तक समय पर पहुंचे, जिससे योजनाओं की प्रभावशीलता में सुधार होता है। इसका मुख्य लक्ष्य पारदर्शिता बढ़ाना है।हरित क्रांति के दौर से पहले किसान प्राकृतिक खेती किया करते थे, जिसमें रासायनिक उर्वरकों की खपत नगण्य थी। उस समय फसलों का उत्पादन और उत्पादकता कम थी। देश के बार-बार अकालग्रस्त होने से, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विदेशी अनाज के आयात पर निर्भर थी। वर्ष 1943 के बंगाल अकाल में 30 लाख से ज्यादा लोग भूख से मारे गए। ऐसी विकट परिस्थितियों में, नीतिकारों ने हरित क्रान्ति के जनक डा. नॉर्मन बोरलॉग द्वारा विकसित गेहूं की बौनी किस्मों और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान से धान की बौनी किस्मों का आयात करके, देश में हरित क्रांति का आगाज किया। इन उन्नत गेहूं-धान की बौनी किस्मों और बाजरा-ज्वार की हाईब्रीड किस्मों से पूरा उत्पादन लेने के लिए, भारी मात्रा में उर्वरकों का आयात और उत्पादन व भूजल आधारित ट्यूबवेल से सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया।**

हरित क्रांति दौर में अपनाए गए कृषि सुधारों से देश में विभिन्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में कई गुणा बढ़ोतरी हुई। जिसकी बदौलत पिछले 5 दशकों से, लगातार बढ़ती आबादी के बावजूद, देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना हुआ है। चावल का पचास हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का वार्षिक निर्यात भी कर रहा है।भारत में वर्ष 2022 में उर्वरक की औसत खपत 193 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि थी और लगभग 30 करोड़ मीट्रिक टन उर्वरक की खपत हुई। भारत में यूरिया सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला उर्वरक है। देश में उर्वरक की खपत प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। उर्वरकों की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए सरकार भारी मात्रा मे वार्षिक आयात करती है।हरियाणा-पंजाब-पश्चिम उत्तर प्रदेश आदि प्रदेशों में गेहूं-धान फसल चक्र की उत्पादकता 10 टन वार्षिक से ज्यादा है। इसी तरह पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल आदि प्रदेशों में भी वार्षिक धान की 2-3 फसल चक्र की उत्पादकता 10 टन से ज्यादा है। इसलिए इन प्रदेशों में उर्वरक की वार्षिक खपत राष्ट्रीय औसत से दुगने से भी ज्यादा प्रति हेक्टेयर 250 किलो नाइट्रोजन, 120 किलो फास्फोरस और 200 किलो पोटेशियम के आसपास है। जबकि वर्षा आधारित बारानी फसलों बाजरा, ज्वार, दलहन, तिलहन आदि के उत्पादक राज्यों में उर्वरक की वार्षिक खपत राष्ट्रीय औसत से काफी कम रहती है। उच्च उत्पादकता वाली कन्दमूल और गन्ने जैसी फसलों को अच्छी पैदावार देने के लिए ज्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिससे इन फसलों की रासायनिक उर्वरक की खपत बहुत ज्यादा होती है।हरित क्रांति दौर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, नीतिकारों ने कृषि क्षेत्र के लिए रासायनिक उर्वरक की सस्ती दर पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उर्वरक सब्सिडी नीति को अपनाया। किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने पर सरकार का व्यय पिछले वित्त वर्ष में 6 प्रतिशत घटकर रुपये 1,77,129.5 करोड़ रह गया, जो 2023-24 के दौरान रुपये 1,88,291.62 करोड़ था। यह गिरावट मुख्य रूप से यूरिया और डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) के आयात में गिरावट तथा अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में कमी के कारण हुई है। गिरावट के बावजूद, वास्तविक सब्सिडी बजट में प्रदान की गई रुपये 1,71,310 करोड़ से 3.4 प्रतिशत अधिक है। यूरिया, जो एक पूर्णतः नियंत्रित उर्वरक है, का विक्रय मूल्य पिछले कई वर्षों से 267 रुपये प्रति (45 किग्रा) बैग पर बना हुआ है।

जब बात हो सेहत की

# उमस भरी गर्मी में राहत आयुर्वेदिक कूल बाथ से

**आयुर्वेदिक जीवनचर्या में नियमित स्नान खास तौर पर महत्वपूर्ण है। जो शरीर में वात, पित्त और कफ संतुलित करता है। वहीं आयुर्वेद के हिसाब से पानी में नीम, पुदीना व शहद-दूध आदि मिलाकर या उबटन लगाकर स्नान के कूलिंग इफेक्ट को दोगुना किया जा सकता है और गर्मी से राहत पाई जा सकती है। जानिये, औषधीय-सुगंधित पदार्थों से स्नान के बारे में दिल्ली स्थित एनडीएमसी आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी में मेडिकल ऑफिसर डॉ. कोमल मलिक से रजनी अरोड़ा की बातचीत।**

**सर्दी हो या गर्मी, नहाना हमारी दिनचर्या का अहम हिस्सा है। खासकर उमस भरे बारिश के मौसम में तो दिन में अक्सर दो बार नहाते हैं। यह मौसम जहां बारिश की ठंडी फुहारों के साथ उमंगें और खुशियां लाता है, वहीं वातावरण पानी के वाष्प कणों और नमी से भरी हवाओं वाला होता है। जिसका असर शरीर से निकलने वाले पसीने पर आसानी से देखा जा सकता है। ऐसे में नहाना हाइजीन के लिहाज से फायदेमंद होने के साथ-साथ गर्मी से राहत पहुंचाने और फ्रेश रखने में भी सहायक है।**

**नीम बाथ**–नीम ऑयल की कुछ बूंदें बाल्टी में भरे पानी में मिला कर नहा सकते हैं। नीम के पत्ते भी नहाने के लिए उपयोगी हैं। इसके लिए एक पतीले में पानी गर्म करें। नीम के पत्ते उसमें डालकर 1–2 घंटे के लिए रख दें। पानी छान लें और उसे बाल्टी में भरे पानी में मिलाकर नहाएं। एंटी बैक्टीरियल, एंटी सेप्टिक, एंटी फंगल, एंटी एलर्जिक जैसे गुणों से भरपूर नीम से स्नान करने पर आपको ठंडक का अहसास तो होता ही है। इस मौसम में होने वाली पित्ती, घमौरियों, एग्जिमा, सोरायसिस जैसी समस्याओं के उपचार में सहायक है। दरअसल, नीम का उपयोग तो किसी भी रूप में पूरे शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्द्धक माना जाता है।

**पुदीना बाथ**–माइक्रोबायल गुणों से भरपूर पुदीने का सेवन ही नहीं, नहाना भी शरीर को ठंडक और ताजगी प्रदान करता है। पतीले में उबले पानी में पुदीने के पत्ते डालकर 1–2 घंटे के लिए रख दें। पानी छान कर नहाने के पानी में मिला लें। आप पुदीने के तेल की कुछ बूंदें भी बाल्टी में भरे पानी में मिलाकर नहा सकते हैं। पुदीने के पत्तों का लेप भी काफी असरदार है। थोड़े–से पानी में पत्ते उबाल कर लेप बना लें। नहाने के बाद लेप शरीर के उन अंगों पर लगाएं, जहां पसीना बहुत आता है। करीब 10 मिनट बाद दोबारा नहा लें। इससे सकिन मुलायम तो महसूस होगी ही, इसके साथ ही सुगंध से तन के साथ मन भी महक उठता है।

**नारियल तेल बाथ**–नहाने के हल्के गुनगुने पानी में कुछ बूंदें नारियल के तेल की मिलाकर नहाने से शरीर को विषैले पदार्थों से मुक्ति और राहत मिलती है। इस बाथ से स्किन चमकदार और मुलायम बनी रहती है। यूं भी नारियल तेल की मालिश शरीर के लिए लाभकारी मानी जाती है तो इसे पानी में डालकर नहाने में तो इसके उपयोग से फायदे होने लाजिमी ही होंगे।

मिल्क और हनी बाथ–मिल्क और हनी बाथ यानी दूध में शहद मिलाकर नहाना करने से स्किन में मॉश्चराइजिंग बैलेंस बना रहता है। स्किन में ग्लो आता है और रंग निखरता है। 2 कप फुल क्रीम मिल्क में 3–4 चम्मच हनी मिलाकर तैयार मिश्रण को पानी में मिलाकर स्नान करें। सप्ताह में 1–2 बार यह बाथ जरूर अपनाएं।

**लैमन बाथ**–पसीने के लिए लैमन बाथ बहुत फायदेमंद है। नीबू के रस को नहाने के पानी में मिला सकते हैं या एक मग्गे में नीबू निचोड़ कर रख लें। स्नान के आखिर में इस नींबू पानी को अपने शरीर पर डाल लें। इससे पसीना कम आने के साथ पसीने की दुर्गन्ध से भी राहत मिलेगी। नहाने के पानी में लैमन सिट्रस ऑयल की कुछ बूंदें मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं।

# अच्छी सेहत की नींव है हेल्दी नाश्ता

**आहार में मौजूद पोषक तत्वों से ही हमारे मन-मस्तिष्क को ताकत मिलती है। भोजन में सुबह का नाश्ता काफी महत्वपूर्ण होता है। हेल्दी ब्रेकफास्ट से ही दिनभर के लिए ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। खासकर युवाओं के लिए नाश्ता सेहत की नींव है।**

**यह सच है कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में डटे रहने के लिए हमें प्रतिदिन कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस चीज के लिए संघर्ष किया जा रहा है, वह मकसद ही कहीं गुम हो गया है। हम बेहतर खाना, बेहतर जीवनशैली आदि के लिए ही संघर्ष करते हैं।**

जबकि आज हमारी जिंदगी में सिवाय संघर्ष और कुछ बाकी नहीं रहा। इन सबमें हम सबसे ज्यादा अपना ही नुकसान कर रहे हैं। खासतौर पर सुबह नाश्ता न करके खुद अपने स्वास्थ्य के साथ जबरदस्त खिलवाड़ कर रहे हैं।

हालांकि आमतौर पर युवास्था में ये सब बातें समझ नहीं आतीं। घर के खाने की बजाय हम बाहरी खाने को ज्यादा महत्व देते हैं। स्नैक्स और जंक फूड तो हमारे फेवरेट फूड में शामिल हो जाते हैं। जबकि खानपान और स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि अच्छी सेहत और आकर्षक शरीर के लिए नियमित रूप से नाश्ता करना जरूरी है। यही नहीं, बाहुबल के लिए भी नाश्ता करना आवश्यक है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो युवास्था में इसका कोई विशेष फर्क नहीं दिखेगा। लेकिन एक उम्र के बाद इसका असर महसूस होगा, जब हम शरीर में कमजोरी महसूस करेंगे। हम अपने दूसरे हमउम्रों की तरह सक्रिय नहीं होंगे और न ही हममें जरा भी भागदौड़ की हिम्मत बची होगी।

इससे बचने का रास्ता यही है कि हम अपने नाश्ते के साथ कोई समझौता न करें। उस स्थिति में भी नहीं, जब हमें काम की वजह से एक सेकेंड सांस लेने की भी फुर्सत न हो। विशेषज्ञों की मानें तो हमारे स्वास्थ्य के लिए सिर्फ नाश्ता करना ही जरूरी नहीं है बल्कि नाश्ते में पौष्टिक आहार का होना भी आवश्यक है।

# खनन कांड में गरमाई फाइलें, अब सीडीओ की एंट्री से हलचल

## आधा-आधा मुनाफा तय कर किया गया अवैध खनन, अब होगी एफआईआर

» ग्रामीण बोले गरीब से बोरी छीनने वाले अफसर, लाखों की चोरी पर खामोश क्यों?

» अधिकारी बोले बक्शे नहीं जाएंगे मिट्टी चोर जल्द होगी बड़ी कार्यवाही

डीपीआरओ ने की थी मौके पर पहुंचकर जांच

उक्त प्लाट धारक को बेची गई थी मिट्टी

**प्रमुख संवाददाता दैनिक स्वराज इंडिया**

**कानपुर। चौबेपुर ब्लॉक के राय गोपालपुर गांव में ग्राम प्रधान राजेश कुमार द्वारा कराए गए अवैध मिट्टी खनन कांड में अब प्रशासन पूरी तरह से हरकत में आ गया है। पहले जहां लोगों को लग रहा था कि यह मामला भी फाइलों में दब जाएगा, कानपुर की सीडीओ दीक्षा जैन के स्पष्ट निर्देशों के बाद आरोपी प्रधान की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है।**

सूत्रों के अनुसार, ग्राम पंचायत की भूमि से सैकड़ों ट्राली मिट्टी निकालकर निजी प्लॉटों में भराव हेतु बेचा गया। इस सौदेबाजी में आधा-आधा मुनाफा बांटने की मौखिक डील भी सामने आई है। आरआरसी सेंटर के भीतर जो खुदाई हुई, वह भी अब राजस्व रिकॉर्ड व डीपीआरओ की जांच रिपोर्ट में दर्ज हो चुकी है।सबसे खास बात यह है कि अब जिम्मेदार अधिकारी इस प्रकरण को 'एक उदाहरण' के रूप में देख रहे हैं, जिससे यह संदेश जाए कि ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। डीपीआरओ की रिपोर्ट के बाद, अब सीडीओ खुद मॉनिटरिंग कर रही हैं।अब गांव के लोगों को उम्मीद है कि इस बार मामला सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेगा। जिन लोगों ने मिट्टी माफिया और प्रधान की सांठगांठ के खिलाफ आवाज उठाई, अब वे प्रशासन की सक्रियता से उत्साहित हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर ये कार्रवाई पूरी तरह से हुई, तो भविष्य में कोई भी जनप्रतिनिधि जनता की संपत्ति को निजी कमाई का ज़रिया नहीं बना पाएगा।

### अधिकारी का बयान

**प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार ग्राम प्रधान द्वारा अवैध खनन की पुष्टि हुई है। मैंने डीपीआरओ और एसडीएम से बात की है। जल्द ही संबंधित प्रधान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और पूरे मामले की गहराई से जांच होगी। शासन की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत दोषियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। (सीडीओ कानपुर दीक्षा जैन)**

आरोपी प्रधान राजेश कुमार

# कागज़ पर स्वच्छता, ज़मीन पर सड़ांध आरआरसी सेंटर बदहाल

» स्वच्छ भारत की जमीनी हकीकत सेंटर वीरान, कूड़ा यथास्थान

» ग्राम प्रधान और सचिवों की लापरवाही से योजना दम तोड़ रही

» डीपीआरओ बोले बजट के इंतजार में बंद पड़े हैं सेंटर

**स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो**

कानपुर देहात। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां हर मंच से गांवों को विकसित करने और स्वच्छ भारत मिशन को गति देने की बातें कर रही है, वहीं जमीनी हकीकत इसके एकदम उलट दिखाई दे रही है। कानपुर देहात के ब्लॉक क्षेत्रों में लाखों रुपये खर्च कर बनाए गए रिसोर्स रिकवरी सेंटर इन दिनों सिर्फ वीरानी और खस्ताहाली की तस्वीर पेश कर रहे हैं। कहीं दरवाजों पर ताले लटके हैं तो कहीं

दीवारों पर घास-फूस उग आया है। सबसे बड़ी बात, गांवों के लोगों को ये तक नहीं पता कि ये सेंटर आखिर बने क्यों थे।

अमरौधा विकासखंड सहित दर्जनों ग्राम पंचायतों में बने आरआरसी सेंटर या तो बंद पड़े हैं या फिर स्थानीय बच्चों का अड्डा बन चुके हैं।

कई स्थानों पर इन्हें गोदाम के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। शासन के निर्देशों और समीक्षा बैठकों के बाद भी ग्राम प्रधानों और पंचायत सचिवों की लापरवाही से यह योजना पूरी तरह दिशाहीन हो गई है।

जबाबदेही की जगह बहाना बजट नहीं है तो काम कैसे चलेगा?

जब इस बाबत जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ)

विकास पटेल से सवाल किया गया तो उन्होंने बजट की कमी को वजह बताया। उनका कहना था कि दिसंबर से बजट उपलब्ध नहीं है, जिससे संचालन रुक गया है, परंतु जुलाई से बजट मिलने की उम्मीद है।

बड़ा सवाल यह है कि जब तक बजट आता है, तब तक ये इमारतें और व्यवस्था पूरी तरह बदहाल और निष्प्रभावी हो चुकी होंगी। सरकार का जीरो टॉलरेंस का दावा, यहां पूरी तरह खोखला साबित हो रहा है।

# मौलिक अधिकारों पर 'मर्जर' का वार, शिक्षक हिमांशु राणा ने उठाई आवाज़

**स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो**

**कानपुर देहात। परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों को कम छात्र संख्या के आधार पर अन्य विद्यालयों में विलय करने के आदेश के खिलाफ प्रदेश भर में विरोध तेज हो गया है। शिक्षकों का कहना है कि सरकार का यह कदम समाज के सबसे कमजोर वर्ग के बच्चों के भविष्य और उनके मौलिक अधिकारों पर सीधा प्रहार है। आरटीई अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। विद्यालय बंद होने से बच्चे शिक्षा से वंचित होंगे।**

इसी को लेकर शिक्षक हिमांशु राणा ने दिल्ली के वरिष्ठ अधिवक्ताओं से गहन कानूनी चर्चा की और सरकार के इस निर्णय को चुनौती देने की रूपरेखा तैयार की है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मचारी होने के नाते शिक्षक स्वयं याचिकाकर्ता नहीं बन सकते, लेकिन वे अभिभावकों के माध्यम से इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे।

> » कम नामांकन के नाम पर शिक्षा व्यवस्था पर संकट
>
> » छात्रों-अभिभावकों को जोड़कर लड़ाई को दिशा देने की तैयारी

**संगठित रणनीति के लिए शिक्षक और अभिभावक मिलकर उतरें मैदान में**

राणा ने शिक्षकों से आह्वान किया है कि वे उन अभिभावकों से संपर्क करें जिनके बच्चों का विद्यालय मर्ज होने के बाद बहुत दूर चला गया है। उन्होंने आग्रह किया कि ऐसे मामलों में बच्चों और अभिभावकों का नाम, आधार कार्ड, पूर्व और नए विद्यालय का नाम, दूरी, और सहमति-पत्र जैसी जानकारी जुटाई जाए ताकि उसे कोर्ट कार्यवाही में उपयोग किया जा सके। राणा ने यह भी कहा कि अलग-अलग कोर्ट केस लड़ने की बजाय सभी लोग संगठित होकर एकजुट याचिका दायर करें। यह किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, बल्कि बेसिक शिक्षा को बचाने की सामूहिक लड़ाई है। उन्होंने चेताया कि यदि आज चुप रहे तो हर सत्र में विद्यालय बंद होंगे और आउटसोर्सिंग को बढ़ावा मिलेगा। यह समायोजन और स्थानांतरण का भ्रम फैलाकर शिक्षकों को गुमराह करने का प्रयास है। अंत में उन्होंने कहा कि जल्द ही लखनऊ या इलाहाबाद में अधिवक्ताओं से मिलकर अगली कानूनी कार्यवाही की जाएगी और हर शिक्षक को अब जिम्मेदारी समझते हुए एकजुट होना होगा।

शिक्षक हिमांशु राणा

## खबर छपी असर दिखा:स्वराज इंडिया की रिपोर्ट पर हरकत में आया PWD

**स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो**

**कानपुर देहात। स्वराज इंडिया की तेज़ और सटीक रिपोर्टिंग ने एक बार फिर प्रशासन को नींद से जगा दिया है। मलासा क्षेत्र के बल्हारामऊ-चांदपुर मार्ग पर सेगुर नदी के पास बना जानलेवा मोड़, जहां आए दिन वाहन फिसलने की घटनाएं हो रही थीं, अब सुरक्षित हो चुका है।**

सड़क चौड़ीकरण के बाद पीडब्लूडी के द्वारा न तो घातक मोड़ों पर संकेतक बोर्ड लगाए थे, न ही गहरी खाई या नालों पर बैरिकेडिंग की कोई व्यवस्था की गई थी।

> » सेगुर नदी मोड़ पर आए दिन हादसे, बिना संकेतक बन रहा था जानलेवा रास्ता
>
> » अफसरों की नींद टूटी, अधिशासी अभियंता ने दिए मरम्मत के सख्त आदेश

इससे आम राहगीरों की जान रोज़ खतरे में पड़ रही थी। स्वराज इंडिया ने इस गंभीर चूक को उजागर करते हुए प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी।खबर छपते ही लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता हेमन्त कुमार सिंह ने मामले को गंभीरता से लिया।

उन्होंने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को निर्देश देते हुए तत्काल सड़क की कटान की मरम्मत और सुरक्षा उपायों को अमल में लाने के आदेश दिए। परिणामस्वरूप अब उस खतरनाक मोड़ को पार करना पहले की तुलना में कहीं ज्यादा सुरक्षित हो गया है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक सपना देवी द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से प्रकाशित। संपादकः अनूप कुमार RNI No.: UPHIN/2023/86769 | Email: swarajindia2023@gmail.com | Mob: 7800009853, | Website: www.swarajindianews.com | (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे)

# रथयात्रा से पहले नयागंज में साउंड सिस्टम हटाने पर बवाल

## » धरने पर बैठे लोग– पुलिस से हुई तीखी झड़प

**स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो**

**कानपुर। भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथयात्रा से एक दिन पहले नयागंज क्षेत्र में बुधवार रात उस समय तनाव फैल गया जब पुलिस ने शोभायात्रा के लिए लगाए गए डीजे और हाई वॉल्यूम साउंड सिस्टम को हटवाना शुरू किया। पुलिस कार्रवाई के विरोध में स्थानीय धार्मिक संगठनों और भाजपा समर्थकों ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया और रामलला मंदिर के बाहर धरने पर बैठ गए।**

हंगामे की सूचना मिलते ही मौके पर कई थानों की फोर्स, PAC व QRT यूनिट पहुंची। भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बीच प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और साउंड सिस्टम को वापस लगाने की मांग की। स्थिति तनावपूर्ण बनी रही।

**साजिशन कार्रवाई, बोले प्रदर्शनकारी**

प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि प्रशासन ने एकतरफा कार्रवाई करते हुए बिना पूर्व सूचना के साउंड सिस्टम हटवाया।

उन्होंने इसे रथयात्रा की तैयारियों में बाधा पहुंचाने की साजिश करार दिया। कुछ प्रदर्शनकारी देर रात तक मंदिर के बाहर धरने पर जमे रहे और पुलिस अधिकारियों से तीखी बहस भी हुई।

**प्रशासन का पक्षः ध्वनि प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन**

इस बीच, डीसीपी वेस्ट आरती सिंह ने स्पष्ट किया कि कोर्ट के आदेशानुसार ध्वनि सीमा से अधिक आवाज वाले डीजे और साउंड सिस्टम पर प्रतिबंध है। धार्मिक आस्था का सम्मान है, पर कानूनी दायरे में रहकर आयोजन होना चाहिए, उन्होंने कहा। पुलिस के अनुसार, हाई वॉल्यूम डीजे बिना अनुमति लगाए गए थे।

**एफआईआर दर्ज, वीडियो निगरानी में उपद्रवियों की पहचान**

पुलिस ने हंगामे और रोड जाम में शामिल 140 से अधिक लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। सीसीटीवी फुटेज और ड्रोन कैमरों के जरिए उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। कुछ स्थानों पर पथराव और जूता फेंकने की भी शिकायतें आई हैं, जिनकी जांच जारी है।

**रथयात्रा के लिए भारी सुरक्षा इंतजाम**

प्रशासन ने रथयात्रा के सुचारु आयोजन के लिए पूरे मार्ग पर ड्रोन से निगरानी, सीसी टीवी कैमरे, और धारा 163 बटालियन के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। डीजे साउंड की अनुमति केवल निर्धारित सीमा तक दी जाएगी।

# लव मैरिज के 8 साल बाद पत्नी प्रेमी के साथ भागी

**स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो**

बाराबंकी। एक युवक और युवती ने 8 साल पहले एक–दूसरे से लंबे प्यार–मोहब्बत वाले रिलेशन के बाद शादी करने का फैसला किया था। दोनों प्यार को शादी वाले रिश्ते तक अंजाम तक पहुंचाने के लिए घरवालों से भी भिड़ गए थे 8 साल बाद पत्नी दूसरे प्रेमी के साथ भाग गई। पूरा मामला जनपद फैजाबाद के पूराकलन्दर थाना क्षेत्र में लव मैरिज के 8 साल बाद महिला अपने दूसरी प्रेमी के साथ फरार हो गई। दसौली की 26

## » महिला के दो बच्चे भी हैं मामले की शिकायत पति ने पुलिस को दी है

वर्षीय महिला ने अपने पति के साथ गांव में रहने के दौरान दूसरे युवक से प्रेम हो था। अब उसके साथ वह शादी की नीयत से फरार हो गई। महिला के दो बच्चे भी है मामले की शिकायत पति ने पुलिस को दी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर उसकी गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। इधर पति ने भी तलाश शुरू की तो पत्नी सुबेहा थाना क्षेत्र के मरुई पंचायत के राजापुर गांव में अपने प्रेमी रोहित के साथ मिली पति रामकुमार मिश्रा पुत्र रमाकांत मिश्रा दसौली थाना पूरा कलन्दर जनपद फैजाबाद ने जब पत्नी को घर चलने के लिए कहा तो प्रेमी और पत्नी ने रामकुमार के ऊपर हमला कर दिया राम कुमार ने थाना सुबेहा में शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है

# कान्हा गौशाला में वृक्षारोपण अभियान के तरह रोपे 2100 पौधे

» नगर आयुक्त ने कहा कि कान्हा गौशाला सिर्फ गौवंश संरक्षण का नहीं, बल्कि पर्यावरण संवर्धन का भी एक मॉडल केंद्र बन रही है।

**स्वराज इंडिया संवाददाता**

कानपुर। पर्यावरण संरक्षण और गौवंश कल्याण को लेकर एक अनूठी पहल के तहत आज दिनांक 27 जून 2025 को कानपुर नगर निगम द्वारा संचालित कान्हा गौशाला, किशनपुर में विशेष वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया गया। नगर आयुक्त के निर्देश पर आयोजित इस कार्यक्रम में 2100 से अधिक छायादार और औषधीय वृक्षों का रोपण किया गया।

इस वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत नीम, पीपल, अर्जुन, बरगद, आंवला और अशोक जैसी प्रमुख प्रजातियों के पौधे लगाए गए। यह पहल न केवल गौशाला परिसर को हराभरा और स्वच्छ बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन और

जल स्तर बनाए रखने की दिशा में भी एक प्रेरणादायक प्रयास है।

गौरतलब है कि कान्हा गौशाला, जो कि पशु कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत (p.p.w.s. प्रमाणित) संस्था है, वर्तमान में करीब 5000 निराश्रित गौवंशों को आश्रय, चारा, चिकित्सा व देखरेख की सुविधाएँ उपलब्ध करा रही है। गौशाला के उत्तम प्रबंधन और पशु कल्याण के उच्च मानकों की प्रशंसा करते हुए नगर आयुक्त ने कहा-> फ्रकान्हा गौशाला सिर्फ गौवंश संरक्षण का नहीं, बल्कि पर्यावरण संवर्धन का भी एक मॉडल केंद्र बन रही है।

वृक्षारोपण जैसे प्रयास भविष्य की पीढ़ियों को स्वच्छ और हरित वातावरण देने की दिशा में मजबूत कदम हैं।

इस कार्यक्रम में नगर निगम अधिकारियों के साथ-साथ स्थानीय समाजसेवी, पर्यावरण प्रेमी, छात्र-छात्राएं व गौशाला प्रबंधन समिति के सदस्य भी शामिल हुए। प्रतिभागियों ने उत्साह के साथ पौधरोपण में हिस्सा लिया और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को दोहराया।

इस अभियान का उद्देश्य न केवल प्राकृतिक छाया और स्वच्छ वायु प्रदान करना है, बल्कि इसे एक प्रेरणादायक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना है—जिसे अन्य नगर निकाय, पर्यावरण संगठन और पशु कल्याण संस्थाएं भी अपना सकें।

# बाढ़ से पहले तैयारी का अभ्यासः हलिया और बैजामऊ में रेस्क्यू ड्रिल

» आईआरएस प्रणाली पर आधारित मॉक एक्सरसाइज में गोताखोरों और पीएसी ने निभाई अहम भूमिका

» जल स्तर बढ़ने पर गांवों की मुनादी, राहत शिविरों में पहुंचाए गए ग्रामीण

**स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो**

कानपुर देहात। संभावित बाढ़ 2025 के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश के 44 जनपदों में एक साथ आईआरएस प्रणाली आधारित बाढ़ मॉक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी आलोक सिंह के

निर्देशन में जनपद कानपुर देहात के दो स्थानों पर यह मॉक ड्रिल सफलतापूर्वक आयोजित की गई।पहला अभ्यास तहसील भोगनीपुर के ग्राम हलीया में किया गया, जहां बाढ़ जैसी स्थिति में एक व्यक्ति को स्थानीय गोताखोरों व पीएसी की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। मौके पर मौजूद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने घायल व्यक्ति का वहीं उपचार किया और एक अन्य को तत्काल सीएससी रेफर किया गया।

दूसरे चरण में तहसील सिकंदरा के ग्राम बैजामऊ बांगर में मॉक सिचुएशन के तहत यह दर्शाया गया कि नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है और पानी गांव में प्रवेश कर गया है।

ऐसे में प्रशासन द्वारा तत्काल मुनादी कराकर ग्रामीणों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग, राजस्व, पुलिस, बिजली, संचार, बाल विकास, और अन्य सभी विभागों की टीमें मुस्तैद रहीं।

प्रशासन का उद्देश्य इस मॉक ड्रिल के माध्यम से जन सहयोग और विभागीय समन्वय का अभ्यास करना था ताकि आपदा की स्थिति में हर स्तर पर तैयार रहकर जान-माल की रक्षा की जा सके।

# सीधे यमराज के यहां से लग रही महिला मेट की हाजिरी !

» मृत महिला की ऑनलाइन हाजिरी से खुली मनरेगा में भ्रष्टाचार की पोल

»छात्र, रसोईया, भण्डारी को भुगतान, कर्मचारी धृतराष्ट्र अधिकारी भीष्म पितामह

»पकड़े जाने पर मास्टर रोल जीरो, नहीं होती है कार्रवाई

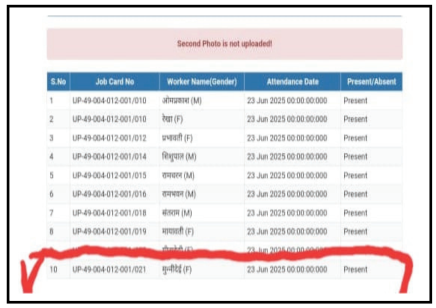

Second Photo is not uploaded!

| S.No | Job Card No | Worker Name(Gender) | Attendance Date | Present/Absent |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UP-49-004-012-001/010 | ओमप्रकाश (M) | 23 Jun 2025 00:00:00:000 | Present |
| 2 | UP-49-004-012-001/010 | रेखा (F) | 23 Jun 2025 00:00:00:000 | Present |
| 3 | UP-49-004-012-001/012 | प्रभावती (F) | 23 Jun 2025 00:00:00:000 | Present |
| 4 | UP-49-004-012-001/014 | शिशुपाल (M) | 23 Jun 2025 00:00:00:000 | Present |
| 5 | UP-49-004-012-001/015 | रामचरन (M) | 23 Jun 2025 00:00:00:000 | Present |
| 6 | UP-49-004-012-001/016 | रामभवन (M) | 23 Jun 2025 00:00:00:000 | Present |
| 7 | UP-49-004-012-001/018 | संतराम (M) | 23 Jun 2025 00:00:00:000 | Present |
| 8 | UP-49-004-012-001/019 | मायावती (F) | 23 Jun 2025 00:00:00:000 | Present |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 10 | UP-49-004-012-001/021 | मुन्नीदेई (F) | 23 Jun 2025 00:00:00:000 | Present |

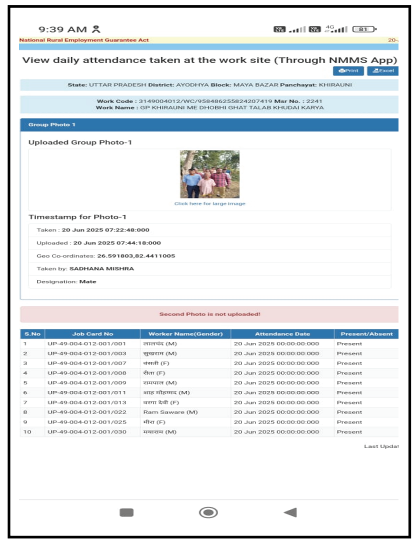

9:39 AM

National Rural Employment Guarantee Act

View daily attendance taken at the work site (Through NMMS App)

Print Excel

State: UTTAR PRADESH District: AYODHYA Block: MAYA BAZAR Panchayat: KHIRAUNI

Work Code : 3149004012/WC/958486255824207419 Msr No. : 2241
Work Name : GP KHIRAUNI ME DHOBHI GHAT TALAB KHUDAI KARYA

Group Photo 1

Uploaded Group Photo-1

Click here for large image

Timestamp for Photo-1

Taken : 20 Jun 2025 07:22:48:000
Uploaded : 20 Jun 2025 07:44:18:000
Geo Co-ordinates: 26.591803,82.4411005
Taken by: SADHANA MISHRA
Designation: Mate

Second Photo is not uploaded!

| S.No | Job Card No | Worker Name(Gender) | Attendance Date | Present/Absent |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UP-49-004-012-001/001 | लालचंद (M) | 20 Jun 2025 00:00:00:000 | Present |
| 2 | UP-49-004-012-001/003 | सुखराम (M) | 20 Jun 2025 00:00:00:000 | Present |
| 3 | UP-49-004-012-001/007 | बंसती (F) | 20 Jun 2025 00:00:00:000 | Present |
| 4 | UP-49-004-012-001/008 | रीता (F) | 20 Jun 2025 00:00:00:000 | Present |
| 5 | UP-49-004-012-001/009 | रामपाल (M) | 20 Jun 2025 00:00:00:000 | Present |
| 6 | UP-49-004-012-001/011 | शाह मोहम्मद (M) | 20 Jun 2025 00:00:00:000 | Present |
| 7 | UP-49-004-012-001/013 | वरमा देवी (F) | 20 Jun 2025 00:00:00:000 | Present |
| 8 | UP-49-004-012-001/022 | Ram Saware (M) | 20 Jun 2025 00:00:00:000 | Present |
| 9 | UP-49-004-012-001/025 | मीरा (F) | 20 Jun 2025 00:00:00:000 | Present |
| 10 | UP-49-004-012-001/030 | मयाराम (M) | 20 Jun 2025 00:00:00:000 | Present |

Last Updat

**स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो**

अयोध्या। विकासखंड मया बाजार अंतर्गत ग्राम पंचायत खिरौनी में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और घोटाले का पर्दाफाश हुआ है मृतक महिला की उपस्थिति दर्ज कराना, छात्रों के नाम पर फर्जी भुगतान और जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही ने पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं।

मनरेगा की निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन (एनएमएमएस) एप से मृतक महिला मुन्नी देवी पत्नी मेवालाल, जिनकी मृत्यु 14 जुलाई 2024 को दर्शन नगर के राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज में हुई थी, की उपस्थिति मास्टर रोल संख्या 2288 में दर्ज की गई। जबकि मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हो चुका है।

ऑनलाइन हाजिरी भरने वाली साधना मिश्रा ने इस अनोखे कारनामे को अंजाम दिया और एक मृतक महिला को मनरेगा में काम करता दिखाकर पूरे सिस्टम को चुनौती दे डाली। साथ ही में मास्टर रोल संख्या 2241, 2242, 2243 मे एक ही फोटो अपलोड की गई है

**मास्टर रोल क्यों किया गया जीरो, अफसरों की भी मिलीभगत**

भ्रष्टाचारियो का मनोबल बढ़ा हुआ है। कर्मचारी धृतराष्ट्र अधिकारी भीष्म पितामह हो तो डर कहे का और ज्ञानमती और लीलावती जो रसोईया और भण्डारी के रूप में कंपोजिट विद्यालय खिरौनी में कार्यरत है साथ ही मास्टर रोल संख्या 2935 पर दर्शाकर भुगतान किया गया, एक ही व्यक्ति एक ही समय में दो सरकारी कार्यों में कैसी दर्ज हो रहे हैं। इतना ही नहीं, शिवम पुत्र सच्चाराम प्रजापति, जो वर्ष 2023 तक एक नियमित छात्र था, उसके नाम पर जॉब कार्ड संख्या 310 दिनांक 04/01/2022 को जारी कर मनरेगा में फर्जी भुगतान किया गया। जबकि उसकी माता चंद्रावती पत्नी सच्चाराम प्रजापति का जॉब कार्ड पहले से ही संख्या 270 दिनांक 20/04/2020 को जारी हो चुका है।

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, कई ग्राम पंचायतों में रोजगार सेवकों काम नहीं दिया जा रहा है बदले में सुविधा शुल्क और मनादेय देना एक संगठित भ्रष्टाचार का संकेत है, जिसमें निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक की मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है। इस घोटाले की परतें तब खुलीं जब श्री चंद्र नामक व्यक्ति ने मुख्य विकास अधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक 16 बिंदुओं पर विस्तृत शिकायत पत्र भेजा। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि किस तरह ग्राम पंचायत खिरौनी सहित अन्य स्थानों पर मनरेगा के नाम पर करोड़ों रुपये का दुरुपयोग किया जा रहा है। (एनएमएमएस) ऐप के जरिये निगरानी के बावजूद मृतक की हाजिरी लगना, छात्र के नाम पर भुगतान और फर्जी जॉब कार्ड जारी होना दर्शाता है कि या तो सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है या फिर भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हैं कि निगरानी तंत्र भी बेबस नजर आ रहा है।

# अयोध्या कलेक्ट्रेट में टावर पर चढ़ा फरियादी

» मामला जमीन के बंटवारे की पैमाइश से जुड़ा है

**स्वराज इंडिया संवाददाता**

अयोध्या शहर की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली कलेक्ट्रेट परिसर शुक्रवार को एक सनसनीखेज घटना का गवाह बना, जब थाना रौनाही क्षेत्र के बरई कला निवासी चन्द्रशेखर यादव उर्फ पप्पू नामक एक फरियादी सीधे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। यह दृश्य किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। नजूल कार्यालय के पास स्थित ऊंचे टावर पर चढ़ा यह व्यक्ति चीख-चीख कर अपनी फरियाद सुनाता रहा – अभिषेक सिंह के खिलाफ की गई मेरी शिकायत पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई?करीब आधे घंटे तक न्याय की गुहार हवा में गूंजती रही। कलेक्ट्रेट कर्मी, वादकारी, अधिवक्ता और राहगीर सकते में खड़े तमाशा बनकर देख रहे थे, मानो सिस्टम की नाकामी का लाइव प्रसारण हो रहा हो। दीवानी न्यायालय चौकी प्रभारी को तत्काल सूचना दी गई, और फिर शुरू हुआ उसे उतारने का 'प्रयास' |मान-मनौव्वल, समझाइश, चेतावनी – पर फरियादी टस से मस नहीं हुआ। वह चाहता था, उसका दर्द नीचे नहीं, ऊपर से सुना जाए। ये घटना सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस लाचार व्यवस्था की चीख है, जिसमें सुनवाई से पहले इंसान को जान दांव पर लगानी पड़ती है।

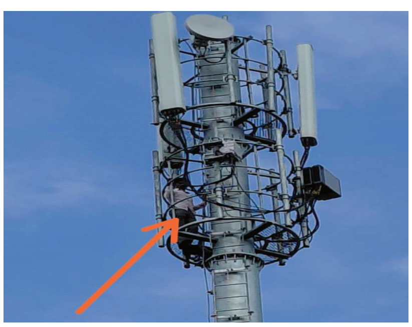

स्वराज इंडिया का सवाल ये है – क्या न्याय के दरवाजे बंद हो चुके हैं, जो अब लोग टावर पर चढ़कर इंसाफ मांग रहे हैं?

या फिर...हमारी प्रशासनिक संवेदनाएं, सिर्फ गिरने पर जागती हैं? इस घटना ने अयोध्या के प्रशासनिक सिस्टम को कठघरे में खड़ा कर दिया है जवाब किसके पास है?

## दस दिनों से भारत में खड़ा ब्रिटेन का एफ-35 फाइटर जेट

# पार्किंग शुल्क वसूल करेगा भारत

### देना होगा 2 करोड़! इस फाइटर जेट को सबसे आधुनिक माना जाता है

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

» त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर 10 दिन से खड़ा है ब्रिटिश एफ-35बी, कई प्रयास पर नहीं उड़ सका

» एयरपोर्ट अथॉरिटी मांगेगी 2 करोड़ की पार्किंग फीस, तकनीकी खराबी के चलते उड़ान पर संशय

» यह जेट शॉर्ट टेक-ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग जैसी विशेषता के लिए दुनिया में जाना जाता है

**नई दिल्ली।** दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट एफ-35बी इस समय केरल के त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर 'पार्क' है। लेकिन अब यह ठहराव ब्रिटिश सरकार को भारी पड़ सकता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी इस सुपरजेट पर 10 दिन की पार्किंग का बिल तैयार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक जो 1.5 से 2 करोड़ रुपए तक हो सकता है।

10 दिन से वीआईपी बे में खड़ा यह जेट आम जेट नहीं बल्कि ब्रिटिश रॉयल नेवी की सैन्य संपत्ति है। एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार चाहे कोई भी विमान हो, एयरपोर्ट की जमीन पर खड़ा है तो चार्ज तो लगेगा और वो भी भारी भरकम।

**पार्किंग नहीं, अब 'महंगी मेहमाननवाजी' बन गया :** एफ-35बी न केवल हाईड्रोलिक खराबी की वजह से फंसा है बल्कि अब ब्रिटिश डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए खर्च का सिरदर्द भी बन गया है। त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट के वीआईपी बे में खड़े इस 15-टन वजनी जेट पर प्रतिदिन का पार्किंग चार्ज 15 से 20 लाख रुपए तक आंका जा रहा है। 10 दिन के हिसाब से बिल 2 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। इसमें ग्राउंड सपोर्ट, सिक्योरिटी, टेक्निकल रिसोर्सेस आदि भी शामिल होंगे। ब्रिटेन और अमेरिका के इंजीनियरों की एक टीम जल्दी ही त्रिवेंद्रम पहुंचेगी ताकि इस तकनीकी गड़बड़ी को दुरुस्त किया जा सके। अगर मरम्मत कामयाब नहीं हुई तो इस जेट को मालवाहक विमान से ट्रांसपोर्ट करने की योजना पर काम शुरू किया जा सकता है।

### भारत के शुक्रगुजार ब्रिटेन, लेकिन जेट अभी भी 'अटका' हुआ है

ब्रिटिश हाई कमीशन के प्रवक्ता ने कहा है, हम भारतीय प्रशासन के समर्थन के लिए आभारी हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही यह समस्या सुलझ जाएगी, लेकिन एयरपोर्ट प्रशासन ने साफ किया है कि 'पार्किंग' के पैसे तो देने ही होंगे। यह पहली बार है जब अमेरिका निर्मित एफ-35बी फाइटर जेट किसी विदेशी जमीन पर इतने दिनों तक खड़ा रह गया है। यह विमान HMS Prince of Wales कैरियर से भारत आया था, जो हाल ही में भारतीय नौसेना के साथ साझा युद्धाभ्यास कर रहा था। यह जेट शॉर्ट टेक-ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग के लिए जाना जाता है और इसे दुनिया का सबसे साइलेंट और घातक फाइटर जेट भी कहा जाता है।

### 110 मिलियन डॉलर कीमत वाला ब्रिटेन का घातक एफ-35 जेट विमान

ब्रिटिश रॉयल नेवी एफ-35बी लाइटनिंग II लड़ाकू विमान, जो 110 मिलियन डॉलर मूल्य की अत्याधुनिक रक्षा परिसंपत्ति है, जो तिरुवनंतपुरम अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टरमैक पर खड़ा धूल फांक रहा है। तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे के बे 4 में खड़े इस ब्रिटिश जेट विमान की सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के जवान कर रहे हैं। शुरू में बताया कि कम ईंधन के कारण उसे आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी, बाद में पता चला कि उसके हाइड्रोलिक सिस्टम में गड़बड़ी थी। ब्रिटिश टीम सहित कई अन्य प्रयासों के बावजूद भी विमान को उड़ान भरने के लिए जमीन पर ही रखा गया है। भारत ने इसे बारिश से बचाने को हैंगर में ले जाने की पेशकश की थी पर रॉयल नेवी ने इनकार कर दिया।

---

**4 घंटे में होगा पोस्टमार्टम**

## परिवार से नहीं लिया जाएगा वीडियोग्राफी का पैसा

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

**लखनऊ।** अब अधिकतम चार घंटे में होगा पोस्टमार्टम, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निर्देश दिया है कि अब पोस्टमार्टम अधिकतम चार घंटे में हो जाए। वहीं, वीडियोग्राफी का पैसा भी पीड़ित परिवार से न लिया जाए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दुःख की घड़ी में परिजनों की पीड़ा कम करने के लिए पोस्टमार्टम को अधिकतम चार घंटे में करने के निर्देश दिए हैं। डिप्टी सीएम के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने पोस्टमार्टम की नई गाइड लाइन जारी कर दी हैं।

प्रदेश भर में अब शव का पोस्टमार्टम अधिकतम चार घंटे में करना होगा। जिन जिलों में अधिक संख्या में पोस्टमार्टम हो रहे हैं। वहां सीएमओ दो या इससे अधिक डॉक्टरों की टीमें बनाकर इस संवेदनशील कार्य को संपन्न कराएं ताकि परिजनों को इंतजार न करना पड़े। डिप्टी सीएम ने बताया कि सूर्यास्त के बाद नियमानुसार पोस्टमार्टम कराया जाए।

जल्द शव के साथ संबंधित अभिलेख भी पोस्टमार्टम हाउस भेजे जाएं। रात में पोस्टमार्टम की दशा में 1000 वॉट लाइट की कृत्रिम व्यवस्था की जाए। अन्य संसाधन भी पर्याप्त हों ताकि 24 घंटे पोस्टमार्टम की कार्रवाई चलती रहे।

---

**एकता-संघर्ष बनी मिसाल**

### पत्रकारों का हल्लाबोल लाया रंग, सरकार ने मानी सभी मांगे

# पेंशन योजना 1 जनवरी 2026 से होगी लागू, दिए आठ तोहफे

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

**लखनऊ।** यूपी की राजधानी लखनऊ आज पत्रकार एकता और संघर्ष की मिसाल बन गई। लंबे समय से चली आ रही पत्रकारों की मांगें आखिरकार रंग लाई हैं। 25 जून को लखनऊ में हुए विशाल आम पत्रकार धरना-प्रदर्शन के ऐन पहले पत्रकारों के प्रतिनिधिमंडल ने सरकार से जबरदस्त वार्ता कर वो ऐतिहासिक सहमति हासिल की, जिसका इंतजार सालों से था।

#### सरकार ने पत्रकारों को दिए 8 बड़े तोहफे

1. जनवरी 2026 से पत्रकार पेंशन योजना होगी लागू, जिला -राज्य मुख्यालय के करीब 148 पत्रकारों की सूची तैयार 2. पीजीआई में पत्रकारों के इलाज के लिए 24 लाख रु. जारी, 2 लाख अतिरिक्त स्वीकृत 3. स्वास्थ्य खर्चों की स्वीकृति के लिए शासनादेश में संशोधन होगा, अब मान्यता प्राप्त पत्रकार कार्ड पर इलाज की सुविधा 4.पत्रकार आवास योजना को मिली मंजूरी, पत्रकार पुरम की तर्ज पर नई योजना लाने पर सहमति 5. पीजीआई में पत्रकारों के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति होगी, स्वास्थ्य उपचार की समस्याओं का त्वरित समाधान। 6. आयुष्मान कार्ड से उपचार में आ रही दिक्कतें सुलझीं, उच्च अधिकारियों ने मौके पर निराकरण किया 7. आकस्मिक मृत्यु पर परिवार को सहायता राशि, नया शासनादेश आएगा, प्रस्ताव स्वीकृति की प्रक्रिया में 8. जिला समन्वय समिति बनेगी, हर जिले में डीएम-एसपी और पत्रकारों की नियमित मासिक बैठक तय।

#### क्या हुआ इस आंदोलन से पहले

पत्रकारों के प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री मा. सुरेश खन्ना से मुलाकात की और मांगों को दस्तावेज़ के रूप में सौंपा। मंत्री जी ने मांगों को तुरंत गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए और अगले ही दिन सूचना निदेशक से बातचीत तय की।25 जून को सूचना निदेशक के साथ हुई लगभग 1 घंटे 15 मिनट की गहन बैठक में पत्रकारों की सभी प्रमुख समस्याओं को एक-एक कर सामने रखा गया और वन-टू-वन समाधान निकाला गया। आंदोलन को नेतृत्व देने वाले पत्रकारों ने सभी साथियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि हमने मांग रखी, सरकार ने मानी। अब निगरानी हमारी जिम्मेदारी है कि वादे ज़मीन पर उतरें। ये सिर्फ एक दिन का आंदोलन नहीं, बल्कि पत्रकारों के सम्मान, सुरक्षा और भविष्य की लड़ाई का जीत है।